क्रम सं०	मद का सारांश	वर्तमान स्थिति
	(ख) भूमि सुधार कार्यान्वयन के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक	इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए कार्यसूची नोट सभी राज्यों के मुख्य सचिवालयों को भेजे जा चुके हैं। इस नोट पर मुख्य मंत्रियों की विशेष बैठक में विचार किया जाएगा, बैठक का आयोजन 11-6-1990 के लिए संभावित है।
	(ग) भू-राजस्व प्रशासन के राष्ट्रीय आयोग का गठन	क्योंकि मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, आयोग के गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।
6.	10 हजार रुपए तक ऋण राहत	निर्णय लिया और घोषित किया गया।
7.	कृषि उत्पाद/खाद्यान्नों के लिए गोदाम का मास्टर प्लान	राज्यों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्-मास्टर प्लान के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा चुका है। राज्यों का मास्टर प्लान तैयार हो जाने के पश्चात् अखिल भारतीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
8.	ग्रामीण समाज पर जोर देने के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	नए कार्यक्रमों का अनुमोदन दिया जा चुका है

राज्यों द्वारा पेड़ काटने की अनुमति

2207. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा: क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 26 दिसम्बर, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 151 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7 दिसम्बर, 1988 को घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अधीन पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने पेड़ संरक्षण अधिनियमों में संशोधन करके पेड़ काटने की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और क्या सरकार देश में पेड़ों को बचाने के लिए कुछ ठोस तथा प्रभावशाली कदम उठाने का विचार रखती है ताकि पेड़ों को काटने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जा सके?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) नई राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह व्यवस्था है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा/नमी वाले वनों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे इलाकों के वनों की पूर्ण सुरक्षा की जानी चाहिए। इस नीति में यह भी कहा गया है कि वन कार्यक्रमों में पर्याप्त रूप से तैयार किए गए प्राकृतिक वनों की स्पष्ट कटाई नहीं की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के अपने वृक्ष सुरक्षा अधिनियम हैं जिन्हें उन्होंने अपनी आवश्यकतानुसार तैयार किया है। निजी भूमियों पर वृक्षों की कटाई को राज्य सरकार के उक्त अधि-

नियमों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य, ग्रामीणों तथा आदिवासियों की ईंधन की लकड़ी, चारा, छोटे वन उत्पाद तथा छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस प्रकार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ वृक्षों की कटाई तो होगी ही और इसलिए वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है।

Location of Central Government Club in Nationa Library Campus in Calcutta

2208. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Central Government club is likely to be located inside the National Library Campus in Calcutta;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to remove the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) No, Sir. There already exists a Central Services Club in the National Library campus, Calcutta for the last thirty years and therefore the question to locate a Central Government club inside the National Library Campus does not arise.

(b) and (c) In view of (a) above, the questions do not arise.

Computers Acquired by CSIR lying unused

2209. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that computers acquired by CSIR for modernising financial and administrative information system at a cost of Rs. 82 lakhs have remained unused;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government propose to take to use these computers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M.G.K. MENON): (a) Out of the 40 Personal Computers systems provided for modernisation of financial and administrative information system in 39 Laboratories and at CSIR Headquarters, all, except in four Laboratories, are now in use.

(b) The delay in these four Laboratories is due to certain hardware and administrative problems.

(c) The remaining four laboratories have been instructed by CSIR to put the Personal Computer systems into use at the earliest.

'Forests in the country'

2210. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to refer to the answer to Starred Question 112 given in the Rajya Sabha on the 20th March, 1990 and state:

(a) what is the minimum per capita requirement of forest cover in the country; and

(b) what steps Government are taking to increase the forest area?